CPI(M)

# जन जोहार झारखण्ड

अंक–05 | मासिक बुलेटिन | अक्टूबर 2022

संपादकीय ....

## स्थानीय जनसमस्याओं पर जारी अभियान को आंदोलन में तब्दील करो

झारखंड में पिछले तीन महीनों से बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के देशव्यापी मुद्दों के साथ–साथ स्थानीय जनसमस्याओं पर प्रभावी अभियान चलाकर राजधानी रांची में भारी वर्षा के बावजूद जनता का महाजुटान आयोजित किया गया। इसी क्रम में पंचपरगना के तमाड़ में जनता की फौरी ज्वलंत जनसमस्याओं पर तीन प्रखंडों को केंद्रित कर एक विशाल जनसभा आयोजित की गई। अब हमें इस अभियान से आगे समस्याओं के हल के लिए जनआंदोलन की दिशा में बढ़ना है। अभी झारखंड सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना के दूसरे फेज के तहत ''आपका अधिकार–आपकी सरकार–आपके द्वार'' कार्यक्रम की घोषणा की है जो दो चरणों में 12 से 22 अक्टूबर और 1 से 14 नवंबर तक राज्य के सभी पंचायतों में आयोजित होगा।

जनसमस्याओं को हल किए जाने की दिशा में राज्य सरकार की इस घोषणा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और प्रशासन द्वारा आयोजित शिविरों में बड़े पैमाने पर जनता से आवेदन दिलाए जाने चाहिए। राज्य सरकार का दावा है कि पिछली बार 35 लाख से ज्यादा आवेदनों पर कार्रवाई कर जनता को राहत दी गई थी। सीपीआई (एम) पार्टी ने जब इस दावे की पड़ताल की तो जो तथ्य सामने आया वह इस दावे की पुष्टि नहीं करता था। इसलिए सीपीआई (एम) ने उस समय ''जनता आपके द्वार'' कार्यक्रम चला कर हजारों आवेदन प्रखंड कार्यालयों में जमा कराए गए थे जिसमें से अभी भी कई आवेदनों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए इस अभियान को अब आंदोलन में तब्दील कर जनता की जीत सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। □

## हालात !

# नए उलगुलान का आह्वान – तमाड़ जनसभा

''ब्रिटिश शासकों और उनके पिट्ठुओं के खिलाफ आदिवासियों और अन्य द्वारा सन् 1782 से 1821 तक चले सबसे लंबे और संघर्षशील 'तमाड़ विद्रोह' की धरती पर आकर मैं गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ''। यह बात आज तमाड़ में आयोजित माकपा की विशाल जनसभा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएँ भी उपस्थित थीं, को संबोधित करते हुए पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात ने कही। झारखंड सीपीआई (एम) की अधिकृत वेबसाइट का उद्घाटन सभा स्थल से हजारों की भीड़ के सामने करने के बाद वे मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों और क्रियाकलापों पर जम कर बरसीं, उन्होंने चौतरफा संकट के लिए मोदी सरकार को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि कमरतोड़ महंगाई और बेरोजगारी ने आम लोगों को घर चलाना मुश्किल कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन सब्जी खरीदते हुए बेशर्मी से अपनी फोटो पोस्ट कर रही हैं, जबकि सब्जी आज अधिकांश आम मेहनतकशों की थाली से गायब है, देश में आधे घरों में दाल नहीं बन रही है। मेहनतकश भात और नमक–मिर्च से अपनी भूख जला कर काम पर निकल रहे हैं। लोगों ने अभूतपूर्व महंगाई के चलते मजबूरी मे अपनी खूराक कम कर दी है। भूख, कुपोषण, खून की कमी और कम शारीरिक विकास के पैमाने पर हमारा देश आज मोदी सरकार की नीतियों के कारण 116 देशों में 101वें स्थान पर शर्मिंदगी के साथ बिलकुल निचली पायदान पर खड़ा है। स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मना रही सरकार का देश के स्वतंत्रता आंदोलन से कभी कोई नाता ही नहीं रहा। इनसे हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मोदी सरकार को चेताया कि समुदायों के बीच नफरत की मुहिम चला कर आप देश की जानता का ध्यान उनके मुख्य मुद्दों – महंगाई, बेकारी, संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों पर हमलों आदि से नहीं भटका सकते, आज रैली में उपास्थित विशाल जनसैलाब इसका गवाह है।

कॉर्पोरेट्स सरकार की मदद और धार्मिक उन्माद की आड़ में विकास के नाम पर झारखंड में आदिवासियों की जमीन धड़ल्ले से लूट कर उन्हें जल–जंगल–जमीन के सामूहिक स्वामित्व से बेदखल करने में लगी है। वन संरक्षण कानून की नियमावली में बदलाव लाकर कॉर्पोरेट्स द्वारा वन भूमि अधिग्रहण में ग्रामसभा के अधिकार को खत्म करना इसी क्रम में एक घृणित साजिश है, जिसका विरोध हमारी पार्टी कर रही है।

झारखंड सरकार पर बोलते हुए बृंदा करात ने कहा कि सांप्रदायिकता विरोधी व भाजपा– विरोधी मुद्दों पर पार्टी हेमंत सोरेन सरकार के साथ है लेकिन आम मेहनतकश के मुद्दों की अनदेखी और इन पर वादाखिलाफी के हम खिलाफ है। रघुवर दास सरकार द्वारा 11 लाख लोगों के राशन कार्ड को आधार और अन्य कारणों से रद्द किया गया, इनमें से 90% लोग सही थे, कोई भूत या ऐसे लोग नहीं थे जिनका अता पता नहीं था। हेमंत सरकार के लगभग तीन बरसों के कार्यकाल में ना उन 11 लाख लोगों के राशन कार्ड रद्द करने की कोई जाँच हुई ना ही कोई कार्रवाई हुई। उल्टे हेमंत सरकार ने 67 हजार राशन कार्ड और रद्द कर दिया है। हम हेमंत सरकार की इस जनविरोधी कार्रवाई का विरोध करते हैं। पिछले दो महीने से झारखंड के मेहनतकशों को राशन भी नहीं मिला है।

डिजीटाईजेशन द्वारा भूमि रेकार्ड्स को ऑनलाईन करने के क्रम ने भारी अनियमितताएँ हुई हैं जिससे बहुत बड़ी संख्या में रैयतधारी प्रभावित हुए हैं। किसी का नाम गलत है, किसी का खाता–खेसरा गलत है, किसी का रिकार्ड ही गायब है। उन्हें रिकार्ड ठीक करने के नाम पर परेशान किया जा रहा है और दलाल मालामाल हो

... शेष पेज 3 पर

# एचईसी में हटिया मजदूर यूनियन अब सबसे बड़ी मान्यता प्राप्त यूनियन

सेंट्रल गवर्मेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल नंबर 1, धनबाद ने अपने 22.02.2022 के जजमेंट में हटिया मजदूर यूनियन (CITU) द्वारा उठाए गए एचईसी प्रबंधन द्वारा यूनियन की मान्यता के सवाल पर, स्टेट लेबर डिपार्टमेंट द्वारा यूनियनों के मेंबरशिप वेरिफिकेशन के नतीजे एचईसी प्रबंधन को भेजने के बावजूद, वेरिफिकेशन में तीसरे स्थान पर आए हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन (INTUC) की मान्यता जारी रखने को अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करार देते हुए एचईसी प्रबंधन को हटिया मजदूर यूनियन और हटिया मजदूर लोक मंच को मान्यता देने और प्रबंधन के संबंधित क्रियाकलापों में शामिल करने का आदेश पारित किया है। ट्रिब्युनल का ये आदेश एचईसी प्रबंधन की तानाशाही और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूर आंदोलन की ऐतिहासिक और निर्णायक जीत है।

केंद्र सरकार की सार्वजनिक संस्थान विरोधी नीतियों का हटिया मजदूर यूनियन विगत ढाई दशकों से आंदोलनों के माध्यम से विरोध करता रहा है। हटिया मजदूर यूनियन दशकों से मातृ उद्योग को बचाने के संघर्ष में लगा है, किन्तु हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन एचईसी प्रबंधन के साथ सहयोग की नीति पर चल रहा है, जिससे एचईसी बंदी के कगार पर पहुँच गया है। माकपा राज्य कमिटी ने झारखण्ड सरकार को एचईसी के अधिग्रहण के लिए स्मार पत्र दिया है जिस पर निर्णय आना अभी बाकी है।

कार्यशील पूँजी का अभाव, बैंक गारंटी ना मिलना, प्रबंधन की उदासीनता और केंद्र सरकार की सार्वजनिक संस्थान विरोधी नीतियों के चलते विश्व प्रसिद्ध मातृ उद्योग एचईसी का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण का काम वर्षों से लंबित है और विगत आठ माह से वेतन न मिलने के बावजूद हटिया मजदूर यूनियन और उसके लड़ाके साथी ''एचईसी बचाओ'' आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। □

– भवन सिंह

# स्थानीयता का पैमाना

बिरसा उलगुलान के बाद सन् 1908 ई. में छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट बना जिसमें ''मुंडारी खुंटकट्टीदार'' का प्रावधान था जो आदिवासियों की जमीन गैर–आदिवासियों के हाथों में जाने से रोकता था। तत्कालीन रांची जिला (मौजूदा रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिला) का पहला भू–सर्वेक्षण 1902 से 1910 ई. तक चला। सर्वेक्षण के बाद जमीन के हर टुकड़े का कागजात बना, जिसे आदिवासियों की मुंडारी, कुडुख, खड़िया या अन्य प्रचलित क्षेत्रीय भाषा में न लिख कर अरबी–फारसी में लिखा गया था। खतियान, काश्तकार, रैयती जमीन, बासकित, गैर मजरूआ आम और खास जैसे न समझने वाले शब्दों की आड़ में इस सर्वेक्षण द्वारा मुंडाओं की हजारों एकड़

...शेष पेज 2 पर

## 1932 खतियान...

...... शेष पृष्ठ 1 का

जमीन सूदखोरों, साहूकारों, जमींदारों, सामंतों और इन जैसे शोषक गैर– आदिवासियों के नाम कर दिया गया। कब्जा किये इन जमीनों के गैर–आदिवासियों को, रातुगढ़ के महाराज का काश्तकार बनाया गया जिसने लगान वसूली के लिए मौजूदा रांची जिले में रातु, सिल्ली, राहे, बेंडा, तमाड़ और जरियागढ़ (खूंटी जिला) में अपना सामंत नियुक्त कर रखा था।

इसी भूमि सर्वे के दौरान 1906–1907 में छोटानागपुर में भीषण अकाल पड़ा, जिससे मुंडा सहित विभिन्न जनजातियों के लोग असम और बर्मा पलायन कर गये थे। उनके लौटने के बाद पता चला कि भू–सर्वे के जरिये हजारों मुंडाओं की जमीन का हेरफेर हुआ, और वे भूमिहीन हो गये थे। 1914–1915 में छोटानागपुर में फिर भीषण अकाल पड़ा, ब्रिटिश सरकार, रातुगढ़ के महाराज और उनके सामंतो से आदिवासियों को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली, उल्टा भूखमरी के दौरान भी लगान वसूली के लिए परेशान किया जाने लगा। इन सब घटनाक्रमों से आदिवासियों में असंतोष था। आक्रोशित आदिवासी लगान देने को तैयार नहीं थे। उन पर पुलिस जुल्म बढ़ता जा रहा था, लगान न देने के कारण इनके खेतों को गैर आदिवासियों में नीलाम किया जाने लगा। भूमिहीन मुंडा लोग पहले ही असम के चाय बगानों की ओर रूख कर चुके थे। रोज–रोज पुलिस जुल्म से त्रस्त रैयत मुंडा लोग भी असम और उत्तरी बंगाल के चाय बगानों की ओर रूख करने लगे।

इसी बीच 1928 से 1932 के बीच फिर से जमीन का सर्वे हुआ। लगान न देने, असम के चाय बगानों में काम करने इत्यादि के कारण हजारों मुंडा फिर खतियान से बंचित हो गये।

आज हर मसले को लेकर 1932 के खतियान पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र के लिए भी 1932 के खतियान को अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है। झारखंड की सत्ता में बैठे मंत्री और ऐसा मांग करने वाले नेता, पराधीनता के दौरान अंग्रेजों के साथ–साथ सूदखोरों, साहूकारों, सामंतों के खिलाफ मुंडाओं के विद्रोह, आदिवासियों के विद्रोह से वाकिफ नहीं हैं। आज एनआरसी द्वारा असम में हजारों मुंडा नागरिकता की सूची से बाहर हो रहे हैं। और ऐसा झारखंड में भी होने वाला है। 1932 खतियान के द्वारा अंग्रेजों और सामंतों के षडयंत्र से अपनी जमीन से बेदखल हुए मुंडा लोग क्या विदेशी हैं?

झारखंड के कई क्षेत्रों में सर्वे नहीं हुए या उनके मुकम्मल दस्तावेज नहीं हैं। माकपा मानती है कि हड़बड़ी में झारखंड सरकार द्वारा झारखंडवासियों के लिए स्थानीयता तय करने के लिए 1932 के खतियान को एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए व्यापकतम स्तर पर व्यापक विमर्श के बाद फैसला लेना उचित होगा।

वैसे भी आदिवासियों का मुख्य मुद्दा उनकी पहचान जल–जंगल–जमीन पर उनका स्वामित्व, पेसा और पाँचवी अनुसूची के तहत उनका संरक्षण, वन संरक्षण कानून के तहत ग्रामसभा द्वारा संरक्षण के साथ–साथ विस्थापन और आरक्षण का है। अशिक्षा और कुपोषण भी उनकी स्थिति को और भयावह बनाते हैं सिर्फ 1932 का खतियान इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। इसीलिए आदिवासियों को एकजुट होकर वर्ग संघर्ष को तेज करना है। बड़ी संख्या में भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोग वनों में

## ग्रामीण बैंक कर्मियों का हड़ताल

ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक ईम्पलाइज एसोसिएशन के आह्वान पर 23 सितंबर शुक्रवार को पूरे देश में 13000 ग्रामीण बैंक कर्मियों का एक दिवसीय हड़ताल सफल रहा। झारखंड के 8 क्षेत्रीय कार्यालय रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, पलामू, गुमला, हजारीबाग, देवघर एवं गोड्डा सभी जगह हड़ताल शत–प्रतिशत सफल रहा। क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष 8 सूत्री माँग के समर्थन में कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने प्रदर्शन किया। इन माँगों में व्यापक स्तर पर निजीकरण के अलावा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, दैनिक एवं अस्थाई रूप से लंबे समय से कार्यरत 13000 कर्मचारियों की सेवा नियमित करना, सार्वजनिक बैंकों की तर्ज पर पूर्ण रूप से द्विपक्षीय समझौता लागू करना, स्टाफ प्रोन्नति नीति में बैंकिंग उद्योग के अनुसार समानता एवं अनुरूप सेवा में छूट, स्पॉन्सर बैंक की व्यवस्था को समाप्त कर राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करना आदि मुख्य हैं।

बैंक ईम्पलाइज फेडरेशन, झारखंड के महामंत्री एम एल सिंह ने इस हड़ताल का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इनकी तमाम न्यायोचित मांगों पर पहल करें अन्यथा आने वाले दिन में और तेज आंदोलन किया जाएगा।□

## जलेस का 10 वां राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न

जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायत राज सभागार में 23 से 25 सितंबर तक जनवादी लेखक संघ का 3 दिवसीय 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन ख्यातिप्राप्त पत्रकार, कृषि संकट के गंभीर अध्येता और बुनियादी विश्लेषक पी साईनाथ ने किया। उन्होंने बतलाया कि मौजूदा निजाम किसानों, मजदूरों तथा आम जनता का विरोधी है। पूंजीपतियों का सहयोगी यह निजाम हमारे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अर्जित मूल्यों एवं अंगीकृत संविधान को भी नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। इस सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए प्रसिद्ध विचारक राम पुनियानी ने मनुवादी फासीवाद की ऐतिहासिक स्रोतों पर प्रकाश डाला। प्रसिद्ध दलित विचारक बिजवाड़ा विल्सन ने व्यवस्था के अंतर्विरोधों का खुलासा किया और कहा कि आज भी हमारे देश में मैनुअल एक्सवैंजिंग (हाथ से गटर साफ करने) की प्रथा जारी है। इस कार्य के दौरान प्रतिवर्ष दर्जनों लोगों की मौत होती है।

वैचारिक सत्र में सभी वक्ताओं ने वर्तमान सरकार द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किए जा रहे हमले और झूठे मुकदमों में फंसाकर कई वर्ष से जेलों में बंद लेखकों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों एवं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की।

उद्घाटन से पूर्व एक प्रभावी नाटक 'तथागत' का मंचन किया गया।

...शेष पेज 3 पर

## मंहगाई–बेरोजगारी के खिलाफ झारखण्ड रैली

भारी वर्षा के बावजूद मंहगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता और जनतांत्रिक हमलों के खिलाफ 20 सितंबर को एचईसी मैदान में राज्य के सभी जिलों से आए माकपा कार्यकर्ताओं की महाजुटान के रूप में अपने उत्कर्ष पर पहुँचा। महाजुटान को संबोधित करते हुए माकपा की पोलिट ब्यूरो सदस्य बृंदा कारात ने कहा कि बुलडोज जनता पार्टी यानि भाजपा को रोकने के लिए माकपा को मजबूत करना जरूरी है। माकपा देश में जनपक्षीय राजनीतिक विकल्प के लिए अभियान चला रही है जिसमें देश के किसानों, मजदूरों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और प्रगतिशील सोच के नागरिकों द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी आंदोलनों से उपजे मूल्यों को एकीकृत कर वाम लोकतांत्रिक विकल्प की ओर बढ़ रही है। यह विकल्प सांप्रदायिक हिंदुत्व व कॉरपोरेट गठबंधन की वर्तमान सरकार जो राष्ट्रीय संपदा की लूट के साथ अपनी विभाजनकारी नीतियों से जनता के बीच दरार पैदा कर रही है, का मुकाबला वर्गीय चेतना का विस्तार और तीखे होते वर्ग–संघर्ष से करेगा।

महाजुटान के पहले सभी राज्य के 24 जिलों से पहुँचे कार्यकर्ताओं का हुजूम झंडा–बैनर के साथ डोरंडा कॉलेज के सामने एकत्रित हुआ जहाँ से तेज बारिश के बावजूद जुलूस निकला और तीन किलोमीटर चल कर महाजुटान स्थल पर पहुँचा। घंटों चले महाजुटान में बेहद खराब मौसम में गगनभेदी नारों के साथ कार्यकर्ता पूरी प्रतिबद्धता से डटे रहे।

महाजुटान में राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने एचईसी को बंदी से बचाने और उसके आधुनिकीकरण के लिए सड़क से संसद तक और एचईसी प्रांगण से राज्यव्यापी लंबे जनआंदोलन का प्रस्ताव रखा जिसे महाजुटान ने सर्वसम्मति से तालियों की गड़गड़ाहट से पास किया।

.... शेष पेज 3 पर

## भगत सिंह के क्रांतिकारी विचार

इस महीने देश–विदेश में उनका जन्मदिन धूम–धाम से मनाया गया। जगह–जगह उनकी मूर्ति का अनावरण, माल्यार्पण, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि चले। टीवी पर शहीदे आजम भगत सिंह पर दिन भर कार्यक्रम और फिल्में चलीं। उन्हें महान आत्मा और महामानव के रूप में याद किया गया।

भगत सिंह सिर्फ याद करने की नहीं जानने की शख्सियत हैं। भगत सिंह अपने 23 वर्षों की अल्प आयु में और 5–6 वर्षों के क्रांतिकारी जीवन में सशरीर मानव से एक विचार के रूप में उभरे, एक नई जन चेतना के रूप में विकसित हुए। उनके विचार, "अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो किसी के पास प्राइवेट प्रार्पटी नहीं होगी, सबको काम मिलेगा और धर्म व्यक्तिगत विश्वास की चीज होगी, सामूहिक नहीं"।

क्या आज भगत सिंह की जयंती का भोंडा दिखावा करने वालों ने उनका कालजयी लेख "मैं नास्तिक क्यों हूँ" कभी पढ़ी है ? उनकी उक्ति "मैं उस सर्वशक्तिमान सर्वोच्च ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करता हूँ" को अगर पढ़ा होता तो भगत सिंह को महान आत्मा और महामानव जैसे भ्रमित करने वाले शब्दों से कतई संबोधित नहीं करते। भगत सिंह के विचार, "कोई भी व्यक्ति, जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़ा हो,

...शेष पेज 4 पर

### पाठकों से निवेदन.....

जन–जोहार का यह पांचवा अंक है। जन जोहार प्रकाशन टीम अपने पाठकों से बुलेटिन का स्वरूप और समाचार एवं विषय वस्तु पर प्रतिक्रिया और सुझाव की अपेक्षा करता है। आपका सुझाव बुलेटिन को और समृद्ध करेगा।□

# यूबीईए का राज्य सम्मेलन

यूनियन बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन झारखंड स्टेट का आठवां राज्य सम्मेलन 18 सितंबर 2022 को एचआरडीसी हॉल रांची में संपन्न हुआ। कॉमरेड जगन्नाथ चक्रवर्ती ने बैंकिंग उद्योग की वर्तमान समस्या तथा केंद्र सरकार के द्वारा लापरवाही के प्रति सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया तथा यूनियन बैंक के अंतर्गत प्रबंधन की कर्मचारी विरोधी प्रवृत्ति एवं समस्याओं से अवगत कराते हुए आने वाले दिनों में संघर्ष के लिए आह्वान किया। मुख्य अतिथि का. प्रकाश विप्लव, महामंत्री, सीटू झारखंड ने विस्तृत रूप से केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों पर बात रखते हुए आम आवाम एवं मजदूर वर्ग को अपनी जवाबदेही से अवगत कराया। इसके पश्चात मुख्य वक्ता का. पी के सारंगी ने यूनियन बैंक के अंतर्गत प्रबंधन की प्रवृत्ति से अवगत कराते हुए भविष्य में अपने आंदोलन को तेज करने तथा सदस्यता बढ़ाने पर ध्यान आकर्षित किया। रूपा खलखो उपाध्यक्ष बेफी, जयोतिश्वर पांडे अध्यक्ष यूनियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन झारखंड, अभिजीत मलिक व अन्य ने भी सम्बोधित किया।

महामंत्री राजेश कुमार जयसवाल ने प्रतिवेदन रखा तथा रतन कुमार कोषाध्यक्ष ने आय–व्यय का विवरण रखा। सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास हुए जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण का विरोध, श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने एवं सेवानिवृत्त कर्मियों का पेंशन अपडेशन, अस्थाई एवं दैनिक मजदूरों की सेवा स्थाई करने, आदि प्रमुख थे। यूनियन के संविधान में भी कुछ संशोधन भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। साथ ही आने वाले दिनों में लड़ाई तेज करने का भी निर्णय लिया गया।

स्वागत भाषण सीटू कोषाध्यक्ष अनिर्बान बोस ने और धन्यवाद ज्ञापन नव निर्वाचित अध्यक्ष ने किया। □

## ...तमाड़ जनसभा

..... शेष पृष्ठ 1 का

रहे हैं। माकपा ने पंचायत स्तर शिविर लगाकर इन त्रुटियोंध् अनियामितताओं को अविलंब ठीक करने की माँग की है। उन्होंने सभा का आह्वान किया कि लाल झंडा के कार्यकर्ता इस मुद्दे पर हेमंत सरकार पर पंचायत स्तर तक दबाव बनाने में अभी से जुट जाएँ।

सभा को संबोधित करते हुए उडीसा के विधायक और माकपा की ओढ़िसा राज्य कमिटी के सदस्य लक्षमण मुंडा ने कहा कि आज मोदी सरकार के संरक्षण मे बड़े कार्पोरेट घराने देश मे जल, जंगल, जमीन और खनिज की लूट के खिलाफ उडीसा से लेकर छत्तीसगढ़ और झारखंड मे विशाल प्रतिरोध आंदोलन खड़ा किया जा रहा है।

सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि आज हेमंत सरकार का महत्वकांक्षी कार्यक्रम "आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार" कार्यक्रम का विज्ञापन अखबारों के मुखपृष्ठ पर छपा है जिसमें पिछले ऐसे ही कार्यक्रम में आए 35 लाख आवेदनों में से लगभग शत प्रतिशत आवेदनों का निपटारा कर देने का दावा सरकार ने किया है। यह दावा गलत है, सिर्फ 25 प्रतिशत आवेदनों पर ही कार्रवाई हुई है। इसी विज्ञापन में ये भी घोषणा हुई की गई है कि भूमि रिकार्ड्स में हुई गड़बड़ी को पंचायत स्तर तक शिविर लगा कर ठीक किया जाएगा। राज्य सचिव ने इसी मुद्दे पर एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें आह्वान किया गया कि अभी से ही भूमि रिकार्ड्स सुधार के काम में लग जाएँ और अगर सरकार इन रिकार्ड्स को ठीक नहीं करती है तो आने वाले दिनों में राँची में एक विशाल प्रदर्शन और जुटान किया जाएगा। प्रस्ताव को जनसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

सभा को राज्य कमिटी सदस्य सुरेश मुंडा ने संबोधित करते हुए 22 वर्ष बाद तमाड़ में माकपा की विशाल रैली में शामिल होने के लिए सबका आभार व्यक्त करते हुए लाल झंडा को तमाड़ में जनसंघर्ष का प्रतीक बनाने का आह्वान किया। सभा को राज्य कमिटी सदस्य सुभाष मुंडा के अलवा बुंडू, तमाड़ और अडकी लोकल कमिटियों के सचिव क्रमशः दिवाकर मुंडा, जहरु मुंडा और गणेश मुंडा ने भी संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता घाषी राम सिंह मुंडा ने की और संचालन रंजीत मोदक ने किया।

सभा से पहले बुंडू टाल प्लाजा से एक बड़ी मोटर साइकिल रैली निकाली गई जो बिरसा मुंडा की मूर्ति पर पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात द्वारा माल्यार्पण करते हुए 16 किलोमीटर दूर तमाड़ बाजार तक पहुँची। तमाड़ बाजार से हजारों की संख्या में लाल झंडे से पटी ये विशाल रैली गुंजायमान जनवादी नारों के साथ बृंदा करात, प्रकाश विप्लव और सुरेश मुंडा के नेतृत्व में लगभग 3 किलोमीटर चल कर तमाड़ मैदान पर पहुँच कर विशाल जनसभा में परिणत हो गई। □

– अमल पांडेय

# एसएफआई पाकुड़ का DEO को स्मार पत्र

12 अक्टूबर 2022 को एसएफआई के बैनर तले पाकुड़ जिला कमेटी ने जैक द्वारा निर्धारित परीक्षा राशि से अधिक राशि छात्र–छात्राओं से लेने के विरोध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्मार पत्र सौंपा।

जैक ने आगामी वर्ष 2023 के लिए छात्र–छात्राओं, आरक्षित तथा अनारक्षित सभी वर्गों के लिए राशि निर्धारित की है, उसके बाबजूद पाकुड़ के कई स्कूल अपने हिसाब से मनमानी राशि ले रहे हैं जो की सरासर गलत है। इस मनमानी राशि वृद्धि के खिलाफ छात्रों और अभिभावकों में काफी रोष है और वे अविलम्ब इस राशि वृद्धि को वापस लेने की मांग करते हैं।

अतः एसएफआई पाकुड़ ने DEO महोदया से मांग किया कि वे उनके मांगों को जल्द से जल्द संज्ञान में ले वरना हम आगे और त्वरित आंदोलन करने पर मजबूर होंगे क्योंकि यह छात्रों के भविष्य का सवाल है। DEO महोदया ने आश्वासन दिया कि वे जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करेंगी ।

आज के इस प्रतिनिधिमंडल में जिला संयोजक नवाब शरीफ, सह संयोजक –जयकुल तथा शबनम खातून, मोदस्सर, रमजान तथा फैसल अहमद आदि उपस्थित थे। □ – अमन

# बीएसएसआर की रैली

दिनांक 19 सितम्बर 2022 को बिहार झारखण्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन (बी एस एस आर यूनियन) के आह्वान पर झारखंड राज्य में दवा विपणन सहित 40 अन्य क्षेत्रों में कार्यरत सभी सेल्स प्रमोशन एम्प्लोईज ने वर्षों से लंबित श्रम संबंधी मांगों को ले कर माननीय श्रम मंत्रालय के समक्ष मार्च निकाला। रैली तपोवन मैदान, निवारनपुर से नेपाल हाउस तक गई और वहां एक सभा और धरना में तब्दील हो गई। इस सभा को विभिन्न संगठनों के नेतृत्वकारी साथियों ने भी संबोधित किया। झारखंड राज्य के कई जिलों से 400 साथियों ने रैली एवं धरना में भाग लिया।

रैली के बाद पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 6 सूत्री मांगों को श्रम सचिव के समक्ष रखा। मांगें हैं – सभी सेल्स प्रमोशन एम्लायज को 26000/– न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, मई दिवस को N.I. Act के तहत अवकाश घोषित करना, महिलाओं के लिए सेल्स प्रमोशन एम्लाइज एक्ट के प्रावधान के तहत 6 महीने का मातृत्व अवकाश घोषित करना, सेल्स प्रमोशन एम्लॉयज एक्ट (Condition of Service Act 1976) के सभी प्रावधानों को सख्ती से लागू करना एवं उलंघनकारी मालिकों को सख्त सजा देना, राज्य सरकार द्वारा घोषित 8 घंटे (9 से 6 बजे) के काम को सख्ती से लागू करना और बोनस–पीएफ–ग्रेच्युटी आदि सुविधाओं को लागू करना। □

# जेएसजीईएफ का 7वां राज्य सम्मेलन

झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 7वां राज्य सम्मेलन 18 सितंबर को रांची के पलाश सभागार में गगनभेदी नारों के साथ शुरू हुआ।

मुख्य अतिथि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी सुभाष लांबा ने कहा कि कोविड महामारी में सरकारी कर्मचारियों ने सबसे अच्छा काम किया। आज 65 प्रतिशत कर्मचारी ठेके पर हैं। केंद्र सरकार रेल, तेल, सेल, भेल, बैंक, कोयला, इस्पात समेत सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण कर आत्मनिर्भर भारत की घोषणा कर रही है। सरकार की नीतियों के कारण महंगाई चरम पर है और आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी आसमान छू रही है, लेकिन भर्ती नहीं किया जा रहा है। आज सारे नौकरी ठेके पर किए जा रहे हैं या फिक्स टर्म नौकरी दिया जा रहा है, जिसमें न पेंशन न सुरक्षा है, इसलिए आने वाले समय में चुनौती बढ़ेगी। जिसका मुकाबला संगठन को मजबूत कर कर्मचारियों के संघर्ष को तेज किया जायेगा।

सीटू के राज्य महासचिव का0 प्रकाश विप्लव ने खुला सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार नया श्रम कानून लाकर मजदूरों को गुलाम बनाने का काम कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 44 श्रम कानूनों में से 29 कानूनों को समाप्त कर चार लेबर कोड में बदल दिया गया, जिससे मजदूर कर्मचारियों का शोषण बढ़ेगा। काम के घंटे 8 के बदले 12 घंटा किया जा रहा है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए फिक्स टर्म रोजगार का विरोध करना होगा। कर्मचारियों को अपनी मांगों के साथ–साथ जनता की मांगों को जोड़ना होगा। धर्म के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है, उसके खिलाफ हमें आगे आना होगा। उद्घाटन सत्र को फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ए श्री कुमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शशीकांत राय, सीटू के राज्य कोषाध्यक्ष अनिर्वाण बोस, संजय पासवान, परिवहन कर्मचारी के नेता के पी राय आदि ने भी संबोधित किया। □

## झारखण्ड रैली ....

..... शेष पृष्ठ 2 का

सभा को पोलित ब्यूरो सदस्य रामचंद्र डोम के अलावा प्रकाश विप्लव और राज्य कमिटी के कई सदस्यों ने संबोधित किया। संचालन सुभाष मुंडा और धन्यवाद ज्ञापन सुफल महतो ने किया। □

## जलेस ....

..... शेष पृष्ठ 2 का

इससे पहले 11 बजे से लेखकों का एक जुलूस गांधी सर्किल से इंदिरा गांधी पंचायत राज कार्यालय तक निकाला गया।

तीन दिनों तक चले इस सम्मेलन में देश के लगभग 237 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें झारखंड से प्रतिनिधियों की संख्या 20 थी। □

# रांची मास्टर प्लान 2037 रद्द करो

14 अक्टूबर 2022 को आदिवासी अधिकार मंच, रांची, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, झारखंड राज्य किसान सभा और झारखंड क्षेत्रीय पड़हा समिति के संयुक्त तत्वावधान में रांची नगर–निगम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन और सभा की गयी। सभा की अध्यक्षता आदिवासी अधिकार मंच के राज्य कोषाध्यक्ष सुखनाथ लोहरा ने किया।

सभा के पूर्व मोरहाबादी मैदान से हजारों की संख्या में जुलूस निकाली गयी जो कचहरी चौक होते हुए रांची नगर निगम कार्यालय के समक्ष सभा में तब्दील हुई। सभा को सम्बोधित करते हुए आदिवासी अधिकार मंच के महासचिव ने कहा कि रांची मास्टर प्लान 2037 से भूमि अधिग्रहण कानून, सीएनटी, पेसा और पांचवी अनुसूची

के उल्लंघन का दुस्साहस कर रही है। आदिवासी उप योजना की राशि का दुरुपयोग कर रही है। आदिवासियों का जीवन तबाह और बर्बाद करने पर तुली है। 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त श्री कुंवर सिंह मुंडा से मिले और सीएनटी विरोधी, पांचवी अनुसूची विरोधी, पेसा कानून और भूमि अधिग्रहण कानून विरोधी रांची मास्टर प्लान 2037 को रद्द करने का स्मार पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में प्रफुल्ल लिंडा, नथानियल होरो, राजेश लिंडा, सुन्दरा स्वामी, बीणा लिंडा, बिरांगी तिग्गा, कृपा एक्का शामिल थे।

सभा में सभी वक्ताओं ने कहा कि 154 गांव के 1.59 लाख एकड़ कृषि भूमि अधिग्रहण होने पर आदिवासियों कृषि रोजगार और पशुधन के समाप्ती होगी। इसका आदिवासियों के जनजीवन और संस्कृति पर दुष्प्रभाव पड़ना लाजमी है। ऐसी परिस्थिति में आदिवासी जनजीवन की सुरक्षा के लिये रांची मास्टर प्लान 2037 को रद्द करने मांग रखी है। □

# तस्वीरों में गतिविधियां ...

## 20 सितम्बर रांची रैली

## 12 अक्टूबर तमाड़ रैली

## अखिल भारतीय किसान सभा राज्य सम्मेलन की ओर ...

रांची जिला किसान सम्मेलन

रांची जिला किसान सम्मेलन

बहरागोड़ा किसान सम्मेलन

बोकारो जिला किसान सम्मेलन

बोकारो जिला किसान सम्मेलन

बोड़ाम किसान सम्मेलन

तोरपा

जामताड़ा

साझा मंच, रांची

कोल्हान जिला सम्मेलन

जलेस, जयपुर

कोडरमा

धनबाद

# भगत सिंह के ....

..... शेष पृष्ठ 2 का

उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा और चुनौती भी देना होगा'' को आज के समाज में परखें तो उनके लिए भद्दी गाली समान प्रतीत होती है। क्या उनकी उक्ति ''धर्म को अलग कर दिया जाए तो राजनीति पर हम सब इकट्ठे हो सकते हैं, धर्मों में हम चाहे अलग–अलग ही रहें'' आज धर्म के नाम पर नफरत की मुहिम चला कर सत्ता पर काबिज होने वालों को पच सकती है ?

भगत सिंह के विचार ''निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार, ये क्रांतिकारी सोच के दो अहम् लक्षण हैं'' और ''क्रांति मानव जाति का एक अपरिहार्य अधिकार है। स्वतंत्रता सभी का एक कभी न खत्म होने वाला जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रम समाज का वास्तविक निर्वाहक है'' आज सत्ता की आलोचना मात्र से लोगों को जेलों में ठूँसने वाली सत्ता और धर्म के नशे में डूबी जनता दोनों को बिलकुल बर्दाश्त नहीं है। और आडंबर यह है कि ये भगतसिंह के जयकारे तो लगाते हैं पर उनके कथन पर अमल नहीं करते।

''जन संघर्ष के लिए, अहिंसा आवश्यक हैं''; ''व्यक्तियों को कुचल कर, वे विचारों को नहीं मार सकते''; ''क्रांति की तलवार तो सिर्फ विचारों की शान से तेज होती है''; ''कानून की पवित्रता तभी तक बनी रह सकती है जब तक वह लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करे''; ''सर्वगत भाईचारा तभी हासिल हो सकता है जब सामाजिक, राजनैतिक एवं व्यक्तिगत समानताएं हों'' जैसे कालजयी विचारों के सृजक और प्रसारक भगत सिंह को एक फोटो, मूर्ति या जन्म–शहादत दिवस तक में समेट देना उनके विचारों के साथ घोर अन्याय है।

क्रांतिकारी विचारों से लैस, सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा और समाजवाद में अटूट विश्वास रखने वाले भगत सिंह 23 मार्च 1931 को अपनी संस्थागत हत्या के बाद क्रांतिकारी विचार में परिवर्तित होकर देश–विदेश की जन चेतना में रच–बस गए। उनके विचार जीवन के हर क्षेत्र में हर पल प्रासंगिक और उपयोगी हैं। आज देश जब स्वतंत्रता को दूसरी लड़ाई लड़ रहा है, भगत सिंह के विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। □

– अमल आजाद

## पार्टी कोष में सहयोग की अपील

संघर्ष कोष के लिये स्वेच्छा से निम्नलिखित बैंक खाते में अपना योगदान करें।

**Communist Party of India Marxist**
**Bank : Bank of Baroda**
**Main Branch, Ranchi**
**A/c No. : 00170200000219**
**IFSC Code : BARB0RANCHI**

सीपीआई (एम) राज्य कमिटी, झारखण्ड की ओर से राज्य सचिव प्रकाश विप्लव द्वारा संपादित एवं प्रेषित। संकलन एवं संयोजन सुधांशु शेखर, अमल पाण्डेय व बिपिन कु0 सिन्हा।
माकपा पार्टी कार्यालय : विश्वकर्मा मंदिर लेन, मेन रोड, रांची–834001, वेबसाईट : cpimjharkhand.org, ई–मेल : janjohar.jharkhand@gmail.com